IX भुगतान और निपटान प्रणालियाँ और सूचना प्रौद्योगिकी

रिज़र्व बैंक ने वर्ष 2024-25 के दौरान भुगतान प्रणालियों की दक्षता, सुरक्षा और पहुँच को बढ़ाने के लिए अपनी पहल जारी रखी, जिससे एक अधिक समावेशी और समुत्थानशील डिजिटल भुगतान ईको सिस्टम को बढ़ावा मिला। भारत की घरेलू भुगतान प्रणालियों, विशेष रूप से एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुँच में तेज़ी लाने के प्रयास जारी रहे। रिज़र्व बैंक अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना प्रदान करने के लिए नवीनतम तकनीक का लाभ उठाएगा।

IX.1 भुगतान विजन दस्तावेजों को आधार मानते हुए[1], रिज़र्व बैंक ने नवाचार और एक सहायक विनियामक ढांचे को बढ़ावा देकर समाज के सभी वर्गों में डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। इस वर्ष भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) की साइबर समुत्थानशीलता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण, धोखाधड़ी की रोकथाम और उपभोक्ताओं के लिए एक सुरक्षित और निर्बाध अनुभव सुनिश्चित करने के लिए उपभोक्ता जागरूकता पर अधिक जोर दिया गया। वैश्विक मोर्चे पर, रिज़र्व बैंक ने यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के लिए विभिन्न रास्ते तलाशे।

IX.2 सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी) ने अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण प्रगति की, जिसमें प्रवाह का शुभारंभ भी शामिल है[2]- प्राधिकरण, लाइसेंस या विनियामक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए रिज़र्व बैंक को आवेदन प्रस्तुत करने के लिए एक केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल। वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई पहल की गईं।

IX.3 इस पृष्ठभूमि में, खंड 2 में 2024-25 के दौरान भुगतान और निपटान प्रणालियों के क्षेत्र में विकास और वर्ष के लिए कार्यसूची के कार्यान्वयन की स्थिति का आकलन शामिल है। खंड 3 में 2024-25 के लिए निर्धारित कार्यसूची के अनुसार डीआईटी द्वारा किए गए विभिन्न उपायों के बारे में बताया गया है। अध्याय को खंड 4 में संक्षेपित किया गया है।

2. भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग

IX.4 वर्ष के दौरान, भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग (डीपीएसएस) ने भुगतान विजन 2025 के अनुरूप अखंडता, समावेशन, नवाचार, संस्थानीकरण और अंतरराष्ट्रीयकरण के स्तंभों पर कई पहल शुरू कीं।

भुगतान प्रणालियाँ

IX.5 भुगतान और निपटान प्रणालियों ने [3]2024-25 के दौरान लेन-देन की मात्रा के संबंध में 34.8 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की, जो पिछले वर्ष में 44 प्रतिशत के विस्तार के शीर्ष पर थी (सारणी IX.1)। मूल्य के संदर्भ में, मुख्य रूप से बड़े मूल्य की भुगतान प्रणाली, जैसे कि, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) में वृद्धि के कारण पिछले वर्ष के 15.8

[1] भुगतान ईको सिस्टम के संरचित विकास को आगे बढ़ाने के लिए कार्यान्वयन रोडमैप के साथ-साथ कार्यनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा वर्ष 2005, 2009, 2010, 2012, 2016, 2019 और 2022 में भुगतान विजन दस्तावेज जारी किए गए।

[2] विनियामक आवेदन, सत्यापन और प्राधिकरण के लिए मंच।

[3] डिजिटल भुगतान और कागज-आधारित लिखतों सहित कुल भुगतान।

सारणी IX.1: भुगतान प्रणाली संकेतक - वार्षिक कारोबार (अप्रैल-मार्च)

मद	मात्रा (लाख में)			मूल्य (₹ लाख करोड़)		
	2022-23	2023-24	2024-25	2022-23	2023-24	2024-25
1	2	3	4	5	6	7
ए. निपटान प्रणाली						
सीसीआईएल संचालित प्रणालियाँ	41	43	47	2,588.0	2,592.1	2,962.2
बी. भुगतान प्रणालियां						
1. बड़े मूल्य के क्रेडिट अंतरण - आरटीजीएस	**2,426**	**2,700**	**3,025**	**1,499.5**	**1,708.9**	**2,013.9**
खुदरा खंड (2 से 6)						
2. क्रेडिट अंतरण	**9,83,621**	**14,86,107**	**20,61,015**	**550.1**	**675.4**	**797.8**
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण)	6	4	4	0.004	0.003	0.002
2.2 एपीबीएस	17,834	25,888	32,964	2.5	3.9	5.5
2.3 ईसीएस क्रेडिट	-	-	-	-	-	-
2.4 आईएमपीएस	56,533	60,053	56,250	55.9	65.0	71.4
2.5 एनएसीएच क्रेडिट	19,257	16,227	16,939	15.4	15.3	16.7
2.6 एनईएफटी	52,847	72,640	96,198	337.2	391.4	443.6
2.7 यूपीआई	8,37,144	13,11,295	18,58,660	139.1	200.0	260.6
3. डेबिट अंतरण और डायरेक्ट डेबिट	**15,343**	**18,250**	**21,660**	**12.9**	**16.9**	**22.1**
3.1 भीम आधार पे	214	194	230	0.1	0.1	0.1
3.2 ईसीएस डेबिट	-	-	-	-	-	-
3.3 एनएसीएच डेबिट	13,503	16,426	19,762	12.8	16.8	22.0
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा हुआ)	1,626	1,629	1,668	0.03	0.03	0.02
4. कार्ड भुगतान	**63,325**	**58,470**	**63,861**	**21.5**	**24.2**	**26.1**
4.1 क्रेडिट कार्ड	29,145	35,610	47,741	14.3	18.3	21.1
4.2 डेबिट कार्ड	34,179	22,860	16,120	7.2	5.9	5.0
5. प्रीपेड भुगतान लिखत	**74,667**	**78,775**	**70,254**	**2.9**	**2.8**	**2.2**
6. कागज़ आधारित लिखत	**7,109**	**6,632**	**6,095**	**71.7**	**72.1**	**71.1**
कुल खुदरा भुगतान (2+3+4+5+6)	11,44,065	16,48,234	**22,22,885**	659.1	791.5	**919.3**
कुल भुगतान (1+2+3+4+5+6)	11,46,491	16,50,934	**22,25,910**	2,158.6	2,500.4	**2,933.1**
कुल डिजिटल भुगतान (1+2+3+4+5)	**11,39,382**	**16,44,302**	**22,19,815**	**2,086.8**	**2,428.2**	**2,862.0**

सीसीआईएल : क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
एपीबीएस : आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम।
आईएमपीएस : तत्काल भुगतान सेवा।
एनईएफटी : राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण।
एनईटीसी : नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन।
एईपीएस : आधार सक्षम भुगतान प्रणाली
ईसीएस : इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस।
एनएसीएच : राष्ट्रीय स्वचालित क्लियरिंग हाउस।
भीम : *भारत* इंटरफेस फॉर मनी।
आरटीजीएस : रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट।
क्रेडिट: क्रेडिट।
डीआर: डेबिट।
- : शून्य/नगण्य।

टिप्पणी: 1. आरटीजीएस प्रणाली में केवल ग्राहक और अंतर-बैंक लेनदेन शामिल हैं।
2. सरकारी प्रतिभूतियों और विदेशी मुद्रा लेनदेन का निपटान भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) के माध्यम से किया जाता है। सरकारी प्रतिभूतियों में सीधे व्यापार और रेपो लेनदेन के दोनों चरण और त्रिपक्षीय रेपो लेनदेन शामिल हैं।
3. कार्ड के आंकड़े प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनलों और ऑनलाइन भुगतान लेनदेन के लिए हैं।
4. संख्याओं को पूर्णांकित करने के कारण स्तंभों में दिए गए आंकड़े कुल संख्या में नहीं जुड़ सकते हैं।

स्रोत: आरबीआई।

प्रतिशत की तुलना में 2024-25 में वृद्धि 17.3 प्रतिशत थी। गैर-नकद खुदरा भुगतान की कुल मात्रा में डिजिटल लेनदेन की हिस्सेदारी वर्ष 2024-25 के दौरान 99.9 प्रतिशत थी (एक वर्ष पहले 99.8 प्रतिशत)।

डिजिटल भुगतान

IX.6 2024-25 के दौरान, आरटीजीएस लेनदेन मात्रा के संदर्भ में 12.0 प्रतिशत और मूल्य के संदर्भ में 17.8 प्रतिशत बढ़ा। खुदरा लेनदेन की मात्रा और मूल्य में क्रमशः 34.9

प्रतिशत और 16.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई (सारणी IX.1)। 31 मार्च 2025 तक, आरटीजीएस सेवाएँ 250 सदस्य बैंकों के 1,73,688 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थीं[4], जबकि एनईएफटी सेवाएँ 236 सदस्य बैंकों के 1,74,762 आईएफएससी के माध्यम से उपलब्ध थीं।

IX.7 खुदरा भुगतान प्रणाली ने 2024-25 में लेनदेन की मात्रा के साथ-साथ मूल्य में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की (सारणी IX.1)। खुदरा भुगतान प्रणाली में, यूपीआई लेनदेन मात्रा के संबंध में 41.7 प्रतिशत और मूल्य के संबंध में 30.3 प्रतिशत बढ़ा, जबकि एनईएफटी लेनदेन मात्रा के

IX.8 संबंध में 32.4 प्रतिशत और मूल्य के संबंध में 13.4 प्रतिशत बढ़ा। मात्रा के संबंध में, 2024-25 के दौरान कुल खुदरा भुगतानों में यूपीआई लेनदेन की हिस्सेदारी सबसे अधिक (84 प्रतिशत) थी। भुगतान अवसंरचना विकास निधि (पीआईडीएफ) ने विशेष रूप से टियर III से टियर VI केंद्रों में स्वीकृति अवसंरचना की उपलब्धता को सब्सिडी देकर वर्ष के दौरान डिजिटल भुगतान में वृद्धि में सहायता की। 2024-25 के दौरान, बिक्री केन्द्रों (पीओएस) टर्मिनलों की संख्या 24.7 प्रतिशत बढ़कर 1.1 करोड़ हो गई। 31 मार्च, 2025 तक यूपीआई क्यूआर कोड 91.5 प्रतिशत बढ़कर 65.8 करोड़ हो गए।

भुगतान प्रणालियों का प्राधिकरण

IX.9 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने 26 ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स (पीए), पाँच पेमेंट एग्रीगेटर्स-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी), 11 गैर-बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) जारीकर्ताओं, एक ट्रेड रिसीवेबल्स एंड डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) इकाई और एक व्हाइट लेबल एटीएम (डब्ल्यूएलए) ऑपरेटर को प्राधिकरण/अनुमोदन प्रदान किया, इसके अलावा कुछ अन्य ऑनलाइन पीए, पीपीआई और डब्ल्यूएलए ऑपरेटर को सैद्धांतिक प्राधिकरण प्रदान किया। इसके अलावा, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान पीपीआई जारी करने के लिए चार बैंकों को भी मंजूरी दी (सारणी IX.2)।

सारणी IX.2: भुगतान प्रणाली ऑपरेटरों (पीएसओ) का प्राधिकरण [मार्च के अंत में]

(संख्या)

इकाइयां	2024	2025
1	2	3
ए. गैर-बैंक – अधिकृत		
पीपीआई जारीकर्ता^	38	48
भुगतान एग्रीगेटर्स-ऑनलाइन$	22	46
भुगतान एग्रीगेटर – क्रॉस बॉर्डर	-	5
डबल्यूएलए ऑपरेटर	4	5
त्वरित धन हस्तांतरण सेवा प्रदाता	1	1
बीबीपीसीयू [एनपीसीआई भारत बिलपे (एनबीबीएल)]	1	1
बीबीपीओयू	10	10
ट्रेड्स प्लेटफ़ॉर्म ऑपरेटर	4	5
एमटीएसएस ऑपरेटर#	8	7
कार्ड नेटवर्क	5	5
एटीएम नेटवर्क	2	2
वित्तीय बाज़ार अवसंरचना	1	1
केंद्रीय प्रतिपक्ष	1	1
खुदरा भुगतान संगठन	1	1
बी. बैंक – स्वीकृत		
पीपीआई जारीकर्ता	59	63
बीबीपीओयू	46	46
एटीएम नेटवर्क	3	3

$: इस अवधि के दौरान दो संस्थाओं ने अपना प्राधिकरण प्रमाणपत्र वापस कर दिया।
#: इस अवधि के दौरान एक संस्था का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया।
^: नियामक आवश्यकता के अनुसार एक इकाई का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया गया।
-: शून्य।
टिप्पणी: पीएसओ में पीपीआई जारीकर्ता, ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर (पीए-ऑनलाइन), भुगतान एग्रीगेटर-क्रॉस बॉर्डर (पीए-सीबी), क्रॉस-बॉर्डर मनी अंतरण (केवल इनबाउंड) सेवा योजनाएं (एमटीएसएस), डब्ल्यूएलए ऑपरेटर, व्यापार प्राप्य डिस्काउंटिंग सिस्टम (टीआरईडीएस) प्लेटफॉर्म, स्वचालित टेलर मशीन (एटीएम) नेटवर्क, त्वरित धन हस्तांतरण सेवा प्रदाता, कार्ड नेटवर्क, भारत बिल भुगतान केंद्रीय इकाई (बीबीपीसीयू), भारत बिल भुगतान परिचालन इकाइयां (बीबीपीओयू) और केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) के अलावा सीसीआईएल और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) शामिल हैं।
स्रोत: आरबीआई।

[4] भारतीय वित्तीय प्रणाली कोड।

वर्ष 2024-25 की कार्यसूची

IX.10 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं:

- भुगतान धोखाधड़ी रिपोर्टिंग के लिए केंद्रीय भुगतान धोखाधड़ी सूचना रजिस्ट्री (सीपीएफआईआर) रिपोर्टिंग को स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों, जिला सहकारी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और गैर-अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) तक विस्तारित किया जाएगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.11]
- चेक ट्रंकेशन सिस्टम (सीटीएस) में दो सेटलमेंट होते थे, एक प्रेजेंटेशन सेशन के लिए और दूसरा रिटर्न सेशन के लिए। ऑन-रियलाइजेशन मॉडल के तहत, सीटीएस की चलनिधि दक्षता में सुधार करने के लिए प्रत्येक बैंक की शुद्ध स्थिति के लिए रिटर्न सेशन के समापन के बाद एक ही सेटलमेंट किया जाएगा (पैराग्राफ IX.12);
- विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) के साथ मिलकर यूपीआई को 20 देशों तक पहुंचाने की दिशा में काम करेगा, जिसकी शुरुआत 2024-25 और समापन 2028-29 तक होगा। इसके अलावा, यूरोपीय संघ और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) जैसे देशों के समूह के साथ फास्ट पेमेंट सिस्टम (एफपीएस) सहयोग के साथ-साथ बहुपक्षीय संबंधों की भी संभावना तलाशी जाएगी (पैराग्राफ IX.13);
- मौजूदा भुगतान ईको सिस्टम (कार्ड नेटवर्क/बैंक/पीपीआई संस्थाएं) ने प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के रूप में एसएमएस-आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) को बड़े पैमाने पर अपनाया है। प्रौद्योगिकी में प्रगति के साथ, भुगतान में धोखाधड़ी और कठिनाई को संबोधित करने के लिए अब विभिन्न अभिनव समाधान उपलब्ध हैं, व्यवहारिक बायोमेट्रिक्स, स्थान/ऐतिहासिक भुगतान, डिजिटल टोकन और इन-ऐप सूचनाओं का लाभ उठाने वाले वैकल्पिक जोखिम-आधारित प्रमाणीकरण तंत्र की खोज की जाएगी (पैराग्राफ IX.14); और
- मौजूदा केंद्रीकृत भुगतान प्रणालियाँ (आरटीजीएस और एनईएफ़टी) धन अंतरण के लिए केवल खाता संख्या और आईएफ़एससी पर निर्भर थीं। धोखाधड़ी को रोकने और भुगतान अनुभव को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से, वास्तविक निधि अंतरण से पहले वास्तविक समय में भुगतानकर्ता के नाम की पुष्टि की शुरुआत को नए अधिनियमित 'डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023' (पैराग्राफ IX.15) के अनुपालन में खोजा जाएगा।

कार्यान्वयन स्थिति

IX.11 सीपीएफआईआर, एक वेब-आधारित भुगतान संबंधी धोखाधड़ी रिपोर्टिंग समाधान है, जिसे 31 मार्च, 2020 से लागू किया गया है। सीपीएफआईआर रिपोर्टिंग सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) [लघु वित्त बैंकों (एसएफबी) और भुगतान बैंकों (पीबी) सहित], गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ताओं और गैर-बैंक क्रेडिट कार्ड जारीकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई थी। अब रिपोर्टिंग को 49 अनुसूचित यूसीबी, सभी स्थानीय क्षेत्र के बैंकों, 43 आरआरबी, 71 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) और 234 गैर-अनुसूचित यूसीबी तक बढ़ा दिया गया है। शेष बैंकों को धीरे-धीरे सीपीएफआईआर रिपोर्टिंग में शामिल किया जा रहा है।

IX.12 चेक समाशोधन की दक्षता में सुधार करने, प्रतिभागियों के लिए निपटान जोखिम को कम करने और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के लिए, रिज़र्व बैंक की विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य (8 अगस्त, 2024) में सीटीएस

के तहत चेकों के निरंतर समाशोधन की घोषणा की गई थी। सीटीएस के तहत निरंतर समाशोधन और ऑन-रियलाइज़ेशन निपटान पर दृष्टिकोण पत्र और तकनीकी विनिर्देश दस्तावेज़ अगस्त 2024 में एनपीसीआई द्वारा सीटीएस सदस्य बैंकों को जारी किए गए थे। एनपीसीआई और बैंक अपने सिस्टम को अपडेट करने की प्रक्रिया में हैं, जिसके बाद गो-लाइव आरंभ किया जाएगा। एक बार लागू होने के बाद, चेक समाशोधन चक्र वर्तमान टी +1 दिन से घटकर कुछ घंटों का हो जाएगा।

IX.13 रिज़र्व बैंक 2028-29 तक यूपीआई को 20 देशों तक ले जाने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है और यूपीआई के साथ-साथ रुपे कार्ड के विस्तार के लिए वैश्विक पहुंच को सुविधाजनक बना रहा है। रिज़र्व बैंक प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हो गया है और एफपीएस (बॉक्स IX.1) को आपस में जोड़ने के लिए अन्य देशों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है।

IX.14 भुगतान ईको सिस्टम को सक्षम बनाने और तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई, 2024 को 'डिजिटल भुगतान लेनदेन के लिए वैकल्पिक प्रमाणीकरण तंत्र' पर एक मसौदा फ्रेमवर्क जारी की।

IX.15 आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के लिए लाभार्थी बैंक खाता जिसका नाम लुक-अप सुविधा है, का आरंभ किए जाने के संबंध में एक परिपत्र 30 दिसंबर, 2024 को जारी किया गया था। यह सुविधा आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम का उपयोग करने वाले धन प्रेषकों को निधि अंतरण शुरू करने से पहले उस बैंक खाते का नाम सत्यापित करने में सक्षम बनाएगी जिसमें पैसा अंतरण किया जा रहा है और इस तरह गलतियों से बचा जा सकेगा और धोखाधड़ी को रोका जा सकेगा। प्रेषक द्वारा दर्ज किए गए लाभार्थी के खाता नंबर और आईएफएससी के आधार पर, यह सुविधा, बैंक के कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सीबीएस) से लाभार्थी के खाते का नाम प्राप्त करेगी। सभी बैंक जो आरटीजीएस और एनईएफटी के प्रत्यक्ष सदस्य या उप-सदस्य हैं, उन्हें 1 अप्रैल, 2025 से पहले यह सुविधा देने की सलाह दी गई थी।

बॉक्स IX.1

प्रोजेक्ट नेक्सस: एक बहुपक्षीय दृष्टिकोण तीव्र भुगतान प्रणालियों (एफपीएस) को आपस में जोड़ना

रिज़र्व बैंक भारत के एफपीएस अर्थात यूपीआई को उनके संबंधित एफपीएस से जोड़ने के लिए विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय सहयोग कर रहा है, ताकि व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) मोड में भुगतान किया जा सके। अब तक, सात देश हैं जो व्यापारी भुगतान के लिए यूपीआई स्वीकार करते हैं, जबकि सिंगापुर के एफपीएस [5]पेनाउ के साथ यूपीआई का जुड़ाव व्यक्तिगत प्रेषण के लिए सक्रिय है।

एफपीएस को द्विपक्षीय रूप से जोड़ने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं: (क) तीव्र वार्ता और कार्यान्वयन; (ख) विशिष्ट आवश्यकताओं के समाधान के लिए अनुकूलित समाधान; और (ग) निरंतर आधार पर दृष्टिकोण को परिष्कृत करना।

एफपीएस को आपस में जोड़ने की दिशा में एक और दृष्टिकोण बहुपक्षीय मंच है, जिसके संसाधन अनुकूलन, प्रक्रियाओं के मानकीकरण और बेहतर मापनीयता के संबंध में फायदे हैं। इन कारकों से प्रेरित होकर और अपने भुगतान प्रणालियों की अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी का विस्तार करने में रिज़र्व बैंक के प्रयासों को और गति प्रदान करने के लिए, भारत जून 2024 में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुआ। प्रोजेक्ट नेक्सस एक बहुपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहल है, जिसकी अवधारणा बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स इनोवेशन हब (बीआईएसआईएच) द्वारा घरेलू एफ़पीएस को आपस में जोड़कर तत्काल सीमा पार खुदरा भुगतान को सक्षम करने के लिए की गई है। भारत के साथ मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड संस्थापक सदस्य देशों के रूप में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुए हैं, जबकि इंडोनेशिया और यूरोपीय सेंट्रल बैंक (ईसीबी) विशेष पर्यवेक्षक हैं। एक बार लाइव होने के बाद, प्रोजेक्ट नेक्सस से लागत कम करते हुए गति, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने पर जी-20 सीमा पार भुगतान रोडमैप में उल्लिखित लक्ष्यों का समर्थन करने की उम्मीद है।

स्रोत: आरबीआई.

[5] भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)।

प्रमुख घटनाक्रम

अखंडता

घरेलू धन अंतरण (डीएमटी) – ढांचे की समीक्षा

IX.16 डीएमटी के लिए रूपरेखा 2011 में औपचारिक बैंकिंग चैनल खोलने के लिए शुरू की गई थी ताकि छोटे मूल्य के घरेलू फंड ट्रांसफर की सुविधा मिल सके और अब उपयोगकर्ताओं के पास फंड ट्रांसफर के लिए कई डिजिटल विकल्प हैं। समीक्षा के आधार पर, मौजूदा डीएमटी रूपरेखा को उचित प्रक्रिया को अनिवार्य करके नकद-आधारित प्रेषण की सुरक्षा बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था: (ए) सत्यापित मोबाइल नंबर और आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (ओवीडी) के साथ प्रेषक का पंजीकरण जैसा कि 'मास्टर दिशानिर्देश -अपने ग्राहक को जानें निर्देश, 2016' में प्रदान किया गया है; (बी) प्रमाणीकरण के अतिरिक्त कारक (एएफए) के साथ प्रत्येक लेनदेन का सत्यापन; और (सी) लेनदेन को नकद आधारित प्रेषण के रूप में वर्गीकृत करने के लिए पहचानकर्ताओं का उपयोग।

आरटीजीएस प्रणाली विनियमों और एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों का अद्यतनीकरण

IX.17 रिज़र्व बैंक ने 25 अक्टूबर 2024 को आरटीजीएस विनियमों और एनईएफटी प्रक्रियात्मक दिशानिर्देशों को संशोधित किया, जिसमें केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (सीपीएस) की सदस्यता के लिए पहुँच मानदंड, सदस्यता की आवधिक समीक्षा, सीपीएस सदस्यों द्वारा निरंतर आधार पर साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन और आरटीजीएस और एनईएफटी से संबंधित मौजूदा परिपत्रों के निर्देश शामिल हैं।

केंद्रीय प्रतिपक्ष (सीसीपी) निर्देश, 2024 में संशोधन

IX.18 रिज़र्व बैंक ने 12 जून 2019 को जारी 'सीसीपी के लिए निर्देश' को निरस्त कर दिया और 28 अक्टूबर 2024 को संशोधित 'सीसीपी के लिए निर्देश' जारी किए, ताकि सीसीपी में कॉर्पोरेट प्रशासन को मज़बूत किया जा सके। निर्देशों में कुछ बड़े बदलावों में बोर्ड की बैठकों के साथ-साथ नामांकन और पारिश्रमिक समिति, जोखिम प्रबंधन समिति और लेखा परीक्षा समिति जैसी महत्वपूर्ण समितियों में स्वतंत्र निदेशकों का प्रतिनिधित्व बढ़ाना शामिल है।

सीपीएस की निगरानी

IX.19 रिज़र्व बैंक के विभिन्न विभागों से लिए गए आंतरिक विशेषज्ञों की एक टीम द्वारा अप्रैल 2024 में सीपीएस का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया था। आरटीजीएस, एक वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई) और एक व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली होने के नाते, वित्तीय बाजार अवसंरचना (पीएफएमआई)[6] के सिद्धांतों के आधार पर मूल्यांकन किया गया था, जैसा कि एफएमआई और खुदरा भुगतान प्रणाली (आरपीएस) के लिए रिज़र्व बैंक के निरीक्षण ढांचे में उल्लिखित है। एनईएफटी प्रणाली, हालांकि एक एफएमआई नहीं है, लेकिन इसका भी पीएफएमआई के आधार पर मूल्यांकन किया गया।

पीएसओ की साइबर समुत्थानशीलता और भुगतान सुरक्षा नियंत्रण

IX.20 मसौदा मास्टर निर्देश पर हितधारकों से प्राप्त फीडबैक के आधार पर, रिज़र्व बैंक द्वारा 30 जुलाई 2024 को गैर-बैंक पीएसओ के लिए साइबर समुत्थानशीलता और डिजिटल भुगतान सुरक्षा नियंत्रण पर अंतिम मास्टर निर्देश जारी किए गए। ये निर्देश साइबर समुत्थानशीलता पर जोर देने के साथ समग्र सूचना सुरक्षा तैयारियों के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करके साइबर सुरक्षा जोखिमों और कमजोरियों की पहचान, विश्लेषण, निगरानी और प्रबंधन के लिए मजबूत शासन तंत्र को शामिल करते हैं।

[6] पीएफएमआई वित्तीय बाजार अवसंरचना के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक हैं, जिन्हें भुगतान और बाजार अवसंरचना समिति (सीपीएमआई) और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (आईओएससीओ) द्वारा अप्रैल 2012 में जारी किया गया था।

क्रॉस-बॉर्डर कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन में प्रमाणीकरण का अतिरिक्त कारक (एएफ़ए) सक्षम करना

IX.21 डिजिटल भुगतान के लिए एएफए की शुरूआत ने लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाया है, जिससे ग्राहकों को डिजिटल भुगतान अपनाने का भरोसा मिला है। हालाँकि, यह आवश्यकता केवल घरेलू लेन-देन के लिए अनिवार्य है। भारत में जारी किए गए कार्डों का उपयोग करके ऑनलाइन अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए समान स्तर की सुरक्षा प्रदान करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने गैर-आवर्ती सीमा पार कार्ड नॉट प्रेजेंट लेनदेन के लिए एएफ़ए को सक्षम करने का प्रस्ताव दिया है, जहां विदेशी व्यापारी या विदेशी अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रमाणीकरण के लिए अनुरोध किया जाता है।

वित्तीय समावेशन

विकलांग व्यक्तियों के लिए डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक पहुंच को सुगम बनाना

IX.22 रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों तक प्रभावी पहुँच को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें भुगतान प्रणाली प्रतिभागियों (पीएसपी) [अर्थात, बैंक और अधिकृत गैर-बैंक भुगतान प्रणाली प्रदाता] को विकलांग व्यक्तियों की पहुँच के संदर्भ में अपनी भुगतान प्रणालियों/लिखतों की समीक्षा करने की सलाह दी गई है। समीक्षा के आधार पर, पीएसपी आवश्यक संशोधन कर सकते हैं ताकि उनके सभी भुगतान सिस्टम और डिवाइस जैसे पीओएस मशीनों तक विकलांग व्यक्तियों द्वारा आसानी से पहुँचा जा सके और उनका उपयोग किया जा सके।

यूपीआई के माध्यम से प्रत्यायोजित भुगतान की शुरूआत

IX.23 'प्रत्यायोजित भुगतान'/'यूपीआई सर्किल' व्यक्तियों (प्राथमिक उपयोगकर्ता) को किसी अन्य व्यक्ति (द्वितीयक उपयोगकर्ता) को प्राथमिक उपयोगकर्ता के बैंक खाते से एक सीमा तक यूपीआई लेनदेन करने की अनुमति देने में सक्षम बनाता है, बिना द्वितीयक उपयोगकर्ता के पास यूपीआई से जुड़े एक अलग बैंक खाता होने की आवश्यकता के। अगस्त 2024 में पेश किया गया यह भुगतान समाधान डिजिटल भुगतान की पहुंच और उपयोग को और गहरा करेगा।

तृतीय-पक्ष एप्लीकेशनों के माध्यम से पीपीआई के लिए यूपीआई एक्सेस

IX.24 रिज़र्व बैंक ने तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से पीपीआई को जोड़ने की अनुमति दे दी है। इससे पीपीआई धारक तीसरे पक्ष के यूपीआई एप्लीकेशन के माध्यम से यूपीआई भुगतान कर सकेंगे/प्राप्त कर सकेंगे।

भुगतान एग्रीगेटर (पीए) - ऑफ़लाइन - मसौदा दिशानिर्देश

IX.25 भुगतान ईकोसिस्टम में पीए की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए मार्च 2020 में उन्हें विनियमन के अंतर्गत लाया गया और उन्हें पीएसओ के रूप में नामित किया गया। तथापि, वर्तमान विनियमन ऑफ़लाइन पीए पर लागू नहीं होते हैं जो निकटता/आमने-सामने के लेन-देन को सक्षम बनाते हैं और डिजिटल भुगतान के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑफ़लाइन पीए पर भी लागू नए मसौदा निर्देश रिज़र्व बैंक की वेबसाइट पर फीडबैक/टिप्पणियों के लिए रखे गए हैं।

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) में बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) भुगतान

IX.26 आज व्यवसायों को एंटरप्राइज़ रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सिस्टम, बी 2बी सेवा प्रदाताओं, फिनटेक और बैंकों के माध्यम से सेवा दी जाती है। ये समाधान वर्तमान में इंटरऑपरेबल नहीं हैं, जिससे इन प्लेटफ़ॉर्म पर भुगतान और चालान का समाधान मुश्किल हो जाता है। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल) द्वारा संचालित बीबीपीएस में बी 2बी को एक श्रेणी के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया। बीबीपीएस के माध्यम से, सिस्टम एक-दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे जिसके चलते मैन्युअल ओवरहेड्स को कम करेंगे।

यूपीआई - सीमाओं में वृद्धि

IX.27 यूपीआई को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु, यूपीआई के निम्नलिखित उत्पादों के लिए सीमाएं बढ़ा दी गईं:

- यूपीआई123पे: हितधारकों के परामर्श से प्रति लेनदेन सीमा ₹5,000 से बढ़ाकर ₹10,000 कर दी गई।
- यूपीआई लाइट : यूपीआई लाइट वॉलेट की प्रति लेनदेन सीमा ₹500 तथा प्रति यूपीआई वॉलेट की कुल सीमा ₹2,000 को बढ़ाकर क्रमशः ₹1,000 तथा ₹5,000 कर दी गई।
- यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान के लिए लेन-देन की सीमा बढ़ाना: यह देखते हुए कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भुगतान नियमित, सामान्य और उच्च मूल्य के हैं, यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा प्रति लेनदेन ₹ 1 लाख से बढ़ाकर ₹ 5 लाख कर दी गई।

यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत ऋण लाइनें - एसएफबी तक दायरा बढ़ाना

IX.28 यूपीआई पर क्रेडिट लाइन्स में 'नए-से-क्रेडिट' ग्राहकों को कम-टिकट, कम-अवधि के उत्पाद उपलब्ध कराने की क्षमता है। एसएफबी अंतिम ग्राहक तक पहुंचने के लिए एक उच्च तकनीक, कम लागत वाले मॉडल का उपयोग करते हैं और यूपीआई पर ऋण की पहुंच का विस्तार करने में एक सक्षम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए, रिज़र्व बैंक ने एसएफबी को यूपीआई के माध्यम से पूर्व-स्वीकृत क्रेडिट लाइनों का विस्तार करने की अनुमति दी।

विभिन्न माध्यमों से जन जागरूकता बढ़ाना

IX.29 वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा 419 इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग जागरूकता और प्रशिक्षण (ई-बात) कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें प्रतिभागियों को इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणालियों के सुरक्षित उपयोग, उनके लाभ और शिकायत निवारण तंत्र के बारे में समझाया गया।

नवाचार

फास्टैग, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (एनसीएमसी) और यूपीआई लाइट की स्वतः पुनःपूर्ति

IX.30 आवर्ती लेनदेन के प्रसंस्करण के लिए ई-अधिदेश ढांचा 10 जनवरी, 2020 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किया गया था, जो निर्धारित आवधिकता के साथ आवर्ती भुगतानों को सक्षम बनाता है। फास्टैग और एनसीएमसी में शेष राशि की पुनःपूर्ति जैसे आवर्ती भुगतान, जिनकी कोई निश्चित आवधिकता नहीं है, और/या समय/राशि विशिष्ट नहीं हैं, को ई-अधिदेश का उपयोग करके स्वचालित रूप से पुनःपूर्ति करने की अनुमति दी गई थी, और आवर्ती लेनदेन के लिए ई- अधिदेश के प्रसंस्करण पर प्री-डेबिट अधिसूचना की आवश्यकता से छूट दी गई थी। रिज़र्व बैंक ने ग्राहक द्वारा निर्धारित सीमा से कम शेष राशि होने पर यूपीआई लाइट वॉलेट को लोड करने के लिए ऑटो-रिप्लेनिशमेंट सुविधा शुरू करके यूपीआई लाइट सुविधा को भी ई-अधिदेश ढांचे के दायरे में लाया।

नकद जमा के लिए यूपीआई

IX.31 बैंकों द्वारा लगाई गई नकद जमा मशीनें (सीडीएम) ग्राहकों की सुविधा को बढ़ाती हैं, साथ ही बैंक शाखाओं पर नकदी-संभालने का भार भी कम करती हैं। यूपीआई की लोकप्रियता और स्वीकार्यता को देखते हुए, जून 2024 से यूपीआई के उपयोग के माध्यम से अंतर-परिचालन योग्य नकद जमा सुविधा आरंभ की गई है।

अंतरराष्ट्रीयकरण

भुगतान प्रणालियों की वैश्विक पहुंच

IX.32 भुगतान विजन दस्तावेज़ 2025 में अंतरराष्ट्रीयकरण स्तंभ के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक के रूप में यूपीआई और रुपे कार्ड की वैश्विक पहुँच का विस्तार करने की परिकल्पना की गई है। रिज़र्व बैंक द्विपक्षीय आधार पर अन्य देशों के एफ़पीएस के साथ यूपीआई को जोड़ने की सुविधा प्रदान कर रहा है,

जिससे आवक और जावक दोनों तरह के प्रेषण भुगतान संभव हो रहे हैं। भूटान, फ्रांस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और यूएई में क्यूआर कोड के माध्यम से भारत के यूपीआई ऐप की स्वीकृति चालू हो गई है, जो अन्य देशों में भारतीय पर्यटकों, छात्रों और व्यवसायिक यात्रियों को उनके भारतीय यूपीआई ऐप का उपयोग करके व्यापारियों को भुगतान करने में सक्षम बनाता है। रुपे कार्ड की स्वीकृति वर्तमान में नेपाल, भूटान, मॉरीशस, सिंगापुर, यूएई और मालदीव में आरंभ है। इसके अलावा, रुपे कार्ड जारी करना भूटान और मॉरीशस में आरंभ हो चुका है और भूटान और मॉरीशस में जारी किए गए रुपे कार्ड भारत में भी स्वीकार्य हैं। रिज़र्व बैंक ने नामीबिया, पेरू, त्रिनिदाद और टोबैगो और जमैका में यूपीआई जैसे बुनियादी ढाँचे की तैनाती के लिए एनआईपीएल को मंज़ूरी दे दी है।

अन्य पहल

एटीएम इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा

IX.33 रिज़र्व बैंक ने समय-समय पर निशुल्क एटीएम लेनदेन की संख्या और अनिवार्य निशुल्क लेनदेन की संख्या से अधिक लेनदेन किए जाने पर ग्राहक पर लगाए जा सकने वाले अधिकतम शुल्क पर विभिन्न निर्देश जारी किए थे। एटीएम लेनदेन के लिए इंटरचेंज शुल्क संरचना पर भी निर्देश जारी किए गए थे। समीक्षा के आधार पर, 'ऑटोमेटेड टेलर मशीनों/कैश रिसाइक्लर मशीनों का उपयोग - इंटरचेंज शुल्क और ग्राहक शुल्क की समीक्षा' पर अद्यतन (28 मार्च, 2025 तक) परिपत्र के अनुसार, यह निर्धारित किया गया है कि एटीएम इंटरचेंज शुल्क एटीएम नेटवर्क्स द्वारा तय किया जाएगा। इसके अलावा 1 मई 2025 से बैंक अनिवार्य नि:शुल्क लेनदेन की संख्या से अधिक लेनदेन करने पर ग्राहकों से प्रति एटीएम लेनदेन अधिकतम ₹23 का शुल्क ले सकते हैं।

डिजिटल भुगतान सूचकांक (डीपीआई)

IX.34 रिज़र्व बैंक ने 2021 में समग्र डीपीआई को निर्मित किया था ताकि देश भर में भुगतान के डिजिटलीकरण की व्याप्ति का पता लगाया जा सके। अर्ध-वार्षिक रूप से गणना की गई आरबीआई-डीपीआई सूचकांक हाल के वर्षों में देश भर में डिजिटल भुगतान को तेज़ी से अपनाने और गहरा करने के लिए महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाता है (चार्ट IX.1)।

पीएसओ का निरीक्षण

IX.35 भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 16 के अंतर्गत, 84 संस्थाओं का ऑनसाइट निरीक्षण किया गया, अर्थात एक वित्तीय बाजार अवसंरचना (सीसीआईएल), एक खुदरा भुगतान संगठन [एनपीसीआई जिसमें एनपीसीआई भारत बिलपे लिमिटेड (एनबीबीएल), रुपे कार्ड्स, एनपीसीआई भीम सर्विसेज लिमिटेड (एनबीएसएल) और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) शामिल हैं], 31 गैर-बैंक पीपीआई जारीकर्ता, 10 बीबीपीओयू, दो टीआरईडीएस प्लेटफॉर्म प्रदाता, एक एटीएम नेटवर्क प्रदाता, 34 ऑनलाइन पीए, एक पीए-सीबी, दो डब्ल्यूएलएओ और तत्काल धन अंतरण (आईएमटी) की सुविधा देने वाली एक

चार्ट IX.1: डिजिटल भुगतान सूचकांक

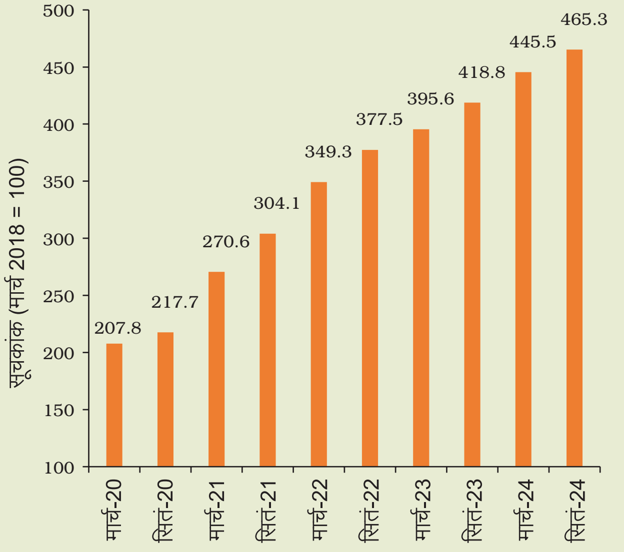

स्रोत: आरबीआई।

संस्था। 2024-25 के दौरान, विभाग ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन/अनुपालन न करने के लिए तीन पीएसओ के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की।

एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड का पहला ऑनसाइट निरीक्षण

IX.36 एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, एक सीसीपी जो त्रिपक्षीय एजेंट के रूप में कार्य करने और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों में कारोबार किए जाने वाले कॉरपोरेट बॉन्ड प्रतिभूतियों में रेपो का निपटान करने के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा अधिकृत है, का ऑनसाइट निरीक्षण जून 2024 में किया गया था। सीसीपी होने के नाते, इकाई का मूल्यांकन पीएफएमआई के विरुद्ध किया गया था।

2025-26 के लिए कार्यसूची

IX.37 2025-26 में विभाग निम्नलिखित लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेगा:

- भारत के डिजिटल भुगतान ईको सिस्टम में उभरते रुझानों, अपनाने के पैटर्न और उपयोगकर्ता की प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने 'डिजिटल भुगतान के उपयोग पर सर्वेक्षण' करने का प्रस्ताव रखा है। उम्मीद है कि इसके निष्कर्षों से लेन-देन के व्यवहार और उपयोगकर्ताओं के समक्ष पेश आने वाली चुनौतियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे वित्तीय समावेशन को बढ़ाने और भुगतान प्रणालियों को और भी अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में सुविधा होगी;
- डिजिटल भुगतान धोखाधड़ी से ग्राहकों को बचाने के लिए, रिज़र्व बैंक ने डिजिटल भुगतान इंटेलिजेंस प्लेटफ़ॉर्म (डीपीआईपी) की स्थापना के विभिन्न पहलुओं की जाँच करने के लिए एक समिति का गठन किया ताकि इस उद्देश्य के लिए उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जा सके। रिज़र्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) को समिति की रिपोर्ट की रूपरेखा के आधार पर पाँच से दस बैंकों के परामर्श से डीपीआईपी का प्रोटोटाइप बनाने का काम सौंपा गया है;
- रिज़र्व बैंक ने 2022 में भुगतान विजन 2025 जारी किया जिसमें दिसंबर 2025 तक की अवधि के लिए रोडमैप का विवरण दिया गया था। 'पेमेंट्स विज़न दस्तावेज़ 2028' को तैयार करने की दिशा में काम शुरू हो गया है और विभिन्न हितधारकों से इनपुट मांगे जा रहे हैं। इस दस्तावेज़ का उद्देश्य पिछले दशक में भुगतान प्रणालियों के विकास को आगे बढ़ाना और भुगतान ईको सिस्टम में संस्थाओं को इस क्षेत्र में समाधान विकसित करने और लागू करने के लिए और अधिक प्रोत्साहन प्रदान करना होगा; औ**र**
- सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए जी-20 रोडमैप ने सीमा पार से भुगतान को सस्ता, तेज, अधिक पारदर्शी और अधिक सुलभ बनाने के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफ़एसबी) द्वारा प्रकाशित 'सीमा पार से भुगतान के लिए लक्ष्यों को पूरा करने पर वार्षिक प्रगति रिपोर्ट: 2024 प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों पर रिपोर्ट' से संकेत मिलता है कि भुगतान की गति के साथ प्राथमिक चुनौती बेनेफिसियरी लेग (*अर्थात*, लाभार्थी बैंक द्वारा भुगतान प्राप्त करने से लेकर अंतिम ग्राहक के खाते में धनराशि जमा होने तक) में अनुभव की जाती है। रिज़र्व बैंक सीमा पार से भुगतान के बेनेफिसियरी लेग की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं की पहचान करने और भारत में संबंधित हितधारकों के परामर्श से उपयुक्त नियामक नीति/कार्रवाई तैयार करने की दिशा में काम करेगा।

3. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डीआईटी)

IX.38 डीआईटी ने रिज़र्व बैंक की सभी आईटी प्रणालियों और एप्लीकेशनों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने और सर्वोत्तम श्रेणी के आईसीटी बुनियादी ढांचे को प्रदान करने के

लिए नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने के लिए अपना प्रयास जारी रखा। सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल प्रवाह को वर्ष के दौरान लाइव किया गया। रिज़र्व बैंक को आंतरिक और बाहरी प्रक्रियाओं में परिवर्तन, पेपर-आधारित वर्कफ़्लो पर निर्भरता कम करने और बैंक में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए सेंट्रल बैंकिंग, लंदन, यूके द्वारा प्रवाह और सारथी के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुना गया है। बाहरी विक्रेताओं पर निर्भरता से जुड़े जोखिमों को कम करने और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान का समर्थन करने के लिए साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान (सीएडी) [सीएडी 2.0] की दूसरी श्रृंखला का शुभारंभ ' साइबर सुरक्षित भारत (#सतर्क नागरिक)' की थीम के साथ किया गया।

2024-25 का कार्यसूची

IX.39 विभाग ने 2024-25 के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए हैं :

- रिज़र्व बैंक ने क्षमता विस्तार की बाधाओं को दूर करने, लगातार बढ़ती आईटी परिदृश्य आवश्यकताओं को पूरा करने और क्षेत्र-विशिष्ट जोखिमों से बचने के लिए एक नए अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर के निर्माण के लिए परियोजना शुरू की। डेटा सेंटर, जिसे रिज़र्व बैंक और उसके सहायक संगठनों की आंतरिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परिकल्पित किया गया है, 2024-25 में अपना परिचालन शुरू करेगा (*उत्कर्ष* 2.0) [पैराग्राफ IX.40];

- भारतीय वित्तीय क्षेत्र के डेटा की सुरक्षा, अखंडता और गोपनीयता को बढ़ाने के लिए, एक क्लाउड सुविधा स्थापित की जाएगी और शुरू में भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी और संबद्ध सेवाओं (आईएफटीएएस) द्वारा इसका संचालन किया जाएगा। इस क्लाउड सुविधा को मध्यम अवधि में कैलिब्रेटेड तरीके से शुरू करने का इरादा है (पैराग्राफ IX.41);

- भारतीय वित्तीय नेटवर्क (आईएनएफ़आईएनईटी) भारतीय बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र के लिए संचार का आधार है। यह सदस्य बैंकों और वित्तीय संस्थानों के अनन्य उपयोग के लिए एक क्लोज्ड उपयोगकर्ता समूह (सीयूजी) नेटवर्क है। आरटीजीएस, एनईएफ़टी और ई-कुबेर जैसे महत्वपूर्ण भुगतान प्रणाली एप्लीकेशन आईएनएफ़आईएनईटी नेटवर्क आधार पर चलते हैं। आईएनएफ़आईएनईटी 3.0 जो बेहतर तकनीक, बैंडविड्थ और समग्र सेवाओं के साथ मौजूदा आईएनएफ़आईएनईटी 2.0 को रिफ्रेश करने का प्रयास करता है, उसे नवीनतम सॉफ्टवेयर-परिभाषित वाइड एरिया नेटवर्क (एसडी-डबल्यूएएन) तकनीक के साथ बनाने का प्रस्ताव है। एसडी-डबल्यूएएन के तहत प्रस्तावित सुविधाओं में लिंक का प्रभावी लोड संतुलन, आवाज और वीडियो ट्रैफ़िक अनुकूलन और एप्लिकेशन जागरूक रूटिंग शामिल हैं। एसडी-वैन नेटवर्क के केंद्रीकृत प्रबंधन और शून्य स्पर्श प्रावधान भी प्रदान करता है (पैराग्राफ IX.42);

- भारतीय रुपये (आईएनआर) को वैश्विक मंच पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक समाधान की परिकल्पना की है, जिसमें भारत की घरेलू संदेश प्रणाली (एसएफएमएस) को वैश्विक एसएफएमएस हब के माध्यम से अन्य देशों तक विस्तारित किया जाएगा। इच्छुक देश अपनी स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार भुगतान संदेश के लिए अपने स्थानीय संदेश प्रणाली को वैश्विक एसएफएमएस हब से जोड़ सकते हैं। इससे भारत को प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है (पैराग्राफ IX.43); और

- 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के साथ तालमेल बिठाने के लिए, विभाग ने बाहरी निर्भरता (विक्रेताओं सहित)

को कम करने के लिए निम्नलिखित एप्लीकेशनों को इन-हाउस विकसित करने की योजना बनाई है, इसके अलावा सिस्टम में परिवर्तन करने के संबंध में समुत्थानशीलता बढ़ायी जाएगी:

- o रिज़र्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड (रेबिट) द्वारा ई-कुबेर 3.0 एप्लीकेशन का विकास। सरकारी भुगतान मॉड्यूल (जीपीएक्स) के साथ कोर एकाउंटिंग प्लेटफॉर्म का विकास प्रगति पर है।
- o घरेलू और साथ ही सीमा पार वित्तीय और गैर-वित्तीय संदेश संचार का समर्थन करने के लिए एक वैकल्पिक संदेश प्रणाली ढांचा विकसित करना। यह सीमा पार समाधान और ऋण पत्र/बैंक गारंटी (एलसी/बीजी) संदेश जैसी कार्यात्मकताओं के साथ विश्व स्तर पर स्वीकृत आईएसओ 20022 संदेश मानकों पर आधारित होगा।
- o डिजिटल भुगतान प्रणालियों के लिए एक वैकल्पिक तंत्र विकसित करें, जो मौजूदा केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली द्वारा वर्तमान में दी जा रही सभी कार्यक्षमताओं के साथ-साथ अन्य उन्नत कार्यक्षमताओं की पेशकश करेगा। यह प्रणाली खुदरा और उच्च मूल्य भुगतान सेवाओं, बल्क मैसेज समर्थन और कम मूल्य की तेज़ भुगतान सेवाओं का समर्थन करेगी। यह सीपीएस से जुड़ने के लिए थिक क्लाइंट और ओपन एपीआई समाधान जैसे विकल्प प्रदान करेगा। इस इन-हाउस विकसित व्यापक प्रणाली को अन्य देशों को भी पेश करने का प्रस्ताव है (पैराग्राफ IX.44).

कार्यान्वयन स्थिति

IX.40 दूसरे ग्रीनफील्ड डेटा सेंटर का निर्माण कार्य अच्छी तरह से चल रहा है। इस सुविधा को उच्च स्तर की अतिरेकता, समुत्थानशीलता और सिस्टम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन और निर्मित किया गया है, जिसमें अंतर्निहित त्रुटि सुधार शामिल है। इसने अपने डिज़ाइन के लिए टियर IV प्रमाणन प्राप्त किया है, जो विश्वसनीयता और प्रदर्शन के उच्चतम मानकों के अनुपालन को रेखांकित करता है।

IX.41 आईएफ़टीएएस को भारतीय वित्तीय क्षेत्र (आईएफ़एस) क्लाउड बनाने का काम सौंपा गया था, जिसका उद्देश्य सुरक्षित और लागत प्रभावी क्लाउड-आधारित सेवाएँ प्रदान करना और आधुनिक तकनीक, शासन और डेटा स्थानीयकरण को अपनाने की चुनौतियों को कम करना था। वर्ष के दौरान आईएफ़एस क्लाउड सेवाओं के चरण I पर काम शुरू किया गया था। साथ ही, न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद (एमपीवी) सेवाओं वाले कुछ बैंकों/वित्तीय मध्यस्थों को शामिल करते हुए आईएफ़एस क्लाउड के बीटा चरण पर काम शुरू हो गया है, ताकि ग्राहक प्रतिक्रिया प्राप्त की जा सके, चुनौतियों को समझा जा सके और क्लाउड सेवाओं की पेशकश को बेहतर बनाने में मदद मिल सके।

IX.42 रिज़र्व बैंक ने आईएफ़टीएएस के माध्यम से आईएनएफ़आईएनईटी 3.0 परियोजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी, फ्रेमवर्क, स्वचालन, बेहतर बैंडविड्थ और समग्र सेवाओं में परिवर्तनकारी बदलावों के साथ मौजूदा आईएनएफ़आईएनईटी 2.0 को ताज़ा करना था। आईएनएफ़आईएनईटी 3.0 समाधान डिज़ाइन में नवीनतम एसडी-डबल्यूएएन तकनीक को अपनाया गया है जो बेहतर ट्रैफ़िक इंजीनियरिंग, एप्लिकेशन दृश्यता और बढ़ी हुई सुरक्षा की अनुमति देता है। वर्तमान में, परियोजना कार्यान्वयन के उन्नत चरण में है।

IX.43 स्थानीय मुद्राओं में सीमा पार भुगतान को सक्षम करने के लिए, रिज़र्व बैंक ने वर्ष के दौरान वैश्विक

एसएफ़एमएस हब का विकास पूरा कर लिया है। इस हब की सेवाओं का उपयोग करके, इच्छुक देश अपने केंद्रीय बैंक या नामित बैंक के माध्यम से भारत में नामित बैंक को/से सीधे वित्तीय संदेश भेज/प्राप्त कर सकते हैं। हब से जुड़ने में रुचि व्यक्त करने वाले देशों के साथ तकनीकी चर्चाएँ वर्तमान में चल रही हैं।

IX.44 ई -कुबेर 3.0 एप्लीकेशन को कई व्यावसायिक और कार्यात्मक मॉड्यूल के साथ-साथ एक एंटरप्राइज़ एप्लीकेशन तकनीकी प्लेटफ़ॉर्म के साथ विकसित किया जा रहा है। जीपीएक्स के हिस्से के रूप में ई-भुगतान और ई-रसीद का विकास वर्ष के दौरान पूरा हो गया था, और कोर एकाउंटिंग प्लेटफ़ॉर्म का कार्यान्वयन चल रहा है।

प्रमुख पहल

प्रवाह - एक सुरक्षित और केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल

IX.45 बेहतर शासन के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की रिज़र्व बैंक की प्रतिबद्धता के एक हिस्से के रूप में, प्रवाह को 28 मई, 2024 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस सुरक्षित, केंद्रीकृत वेब-आधारित पोर्टल ने विनियमित संस्थाओं और व्यक्तियों से आवेदन, अनुरोध और संदर्भों को प्रस्तुत करने और संसाधित करने को डिजिटल बना दिया है, जिससे पारदर्शी तरीके से सेवाओं की निर्बाध और तेज डिलीवरी सुनिश्चित हुई है। प्रवाह को रिज़र्व बैंक के आंतरिक वर्कफ़्लो एप्लिकेशन सारथी के साथ भी एकीकृत किया गया था, जिससे एप्लीकेशनों के संपूर्ण प्रसंस्करण जीवनचक्र का एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण सुनिश्चित हुआ और विनियमित संस्थाओं (आरई) के लिए व्यापार करने में आसानी हुई। आगे बढ़ते हुए, प्रवाह में नियोजित संवर्द्धन में शामिल होंगे: (ए) अपलोड किए गए दस्तावेजों को प्रमाणित करने के लिए आधार आधारित ई-साइन सेवाएं; और (बी) प्रवाह में ही अपने इनपुट प्राप्त करने के लिए अन्य नियामकों और सरकारी एजेंसियों के लिए समर्पित पहुंच।

चिराग : एक जनरेटिव कन्वर्सेशनल एआई टूल

IX.46 उभरती हुई प्रौद्योगिकियों, विशेष रूप से जनरेटिव एआई की क्षमता जो संदर्भ-जागरूक, मानव-जैसी प्रतिक्रियाएँ उत्पन्न कर सकती है और बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकती है, केंद्रीय बैंकिंग परिदृश्य में तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है, जो संचालन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने के लिए परिवर्तनकारी अवसर प्रदान करती है। इस उद्देश्य से, रिज़र्व बैंक ने अपना जनरेटिव एआई प्लेटफ़ॉर्म, चिराग भी विकसित किया है। शुरुआत में सूचना निष्कर्ष और संश्लेषण के लिए एक उपकरण के रूप में डिज़ाइन किया गया, चिराग में एक परिष्कृत ऑर्केस्ट्रेशन परत के रूप में विकसित होने की क्षमता है, जो रिज़र्व बैंक के कार्यों की विस्तृत श्रृंखला से जुड़ी विभिन्न प्रकार की सूचनाओं और डेटा के साथ सहजता से समन्वय करेगा।

सारथी 2.0

IX.47 वर्ष के दौरान, रिज़र्व बैंक ने अपने इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली (अर्थात, सारथी) [सारथी 2.0]। सारथी 2.0 को कई विशेषताओं के साथ कार्यान्वित किया जा रहा है जैसे कि बेहतर उपयोगकर्ता इंटरफ़ेस (यूआई) / उपयोगकर्ता अनुभव (यूएक्स), नवीन वर्कफ़्लो प्रक्रियाएँ, मोबाइल प्रतिक्रियाशीलता, ज्ञान भंडार कार्यक्षमता और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ एकीकरण।

एनईएफटी को आईएसओ 20022 मैसेजिंग मानकों के अनुरूप बनाना

IX.48 रिज़र्व बैंक में एनईएफ़टी प्रणाली 2023 से आईएसओ 20022 संदेश मानकों के अनुरूप है। एनईएफ़टी प्रणाली के 230 से अधिक सदस्य बैंकों को अगस्त 2024 तक आईएनएफ़आईएनईटी प्रारूप संख्या (आईएफ़एन) और

आईएसओ संदेशों के बीच रूपांतरण की सुविधा प्रदान करने वाले कनवर्टर समाधान का उपयोग करके आईएसओ मानकों पर माइग्रेट किया गया था। सदस्य बैंक अब अपने संबंधित कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को आईएसओ 20022 के अनुरूप बनाने की प्रक्रिया में हैं, इस प्रकार, आईएसओ संदेशों का सीधा, एंड-टू-एंड ट्रांसमिशन सक्षम करना। आईएसओ 20022 को अपनाने से घरेलू और विदेशी भुगतान समाधानों में संरचित और विस्तृत डेटा, एंड-टू-एंड ऑटोमेशन, प्रभावी अनुपालन और अंतर-संचालन क्षमता उपलब्ध होगी।

सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) और साइबर सुरक्षा का निरंतर उन्नयन

IX.49 आईटी और साइबर सुरक्षा का उन्नयन डिजिटल खतरों के लगातार विकसित हो रहे परिदृश्य को नेविगेट करने के लिए रिज़र्व बैंक के चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है। सीएडी के हिस्से के रूप में, महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे का प्रबंधन करने वाले अधिकारियों के लिए 'रेड टीमिंग' साइबर सुरक्षा अभ्यास आयोजित किया गया था। रिज़र्व बैंक में दिन-प्रतिदिन के संचालन के दौरान आने वाली समस्याओं/चुनौतियों को दूर करने के लिए नए दृष्टिकोण और तकनीकी समाधान विकसित करने के लिए, एक अखिल भारतीय प्रतियोगिता 'साइबर कोडफेस्ट - लेट्स डेवलप टुगेदर' आयोजित की गई थी। जबकि भुवनेश्वर में एंटरप्राइज कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान (ईसीसीटीआई) का निर्माण, जिसका उद्देश्य रिज़र्व बैंक के भीतर एक सुरक्षित और जिम्मेदार साइबर संस्कृति को बढ़ावा देना है, प्रगति पर है, रिज़र्व बैंक के अधिकारियों के लिए उन्नत प्रशिक्षण कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुके हैं। 25-27 जुलाई, 2024 के दौरान आयोजित आईटी पर एक उच्च स्तरीय सम्मेलन, 'टेक कनेक्ट', वर्तमान तकनीकी रुझानों की खोज और हितधारकों के लाभ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं की व्यापक समझ हासिल करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

2025-26 की कार्यसूची

IX.50 2025-26 के लिए विभाग के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

- वित्तीय क्षेत्र के लिए क्लाउड सुविधा: बुनियादी सेवाओं जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर-एज़-ए-सर्विस, प्लेटफ़ॉर्म-एज़-ए-सर्विस, सॉफ़्टवेयर-एज़-ए-सर्विस, कंटेनर-एज़-ए-सर्विस, स्टोरेज-एज़-ए-सर्विस और पब्लिक इंटरनेट प्रोटोकॉल-एज़-ए-सर्विस के साथ आईएफ़एस क्लाउड का चरण I शुरू किया जाएगा। इसके बाद, एपीआई प्रबंधन, एप्लिकेशन प्रदर्शन प्रबंधन, उपलब्धता क्षेत्र और विकास, सुरक्षा और संचालन (डेवसेकऑप्स) जैसी उन्नत सेवाओं के साथ क्लाउड के चरण II पर काम शुरू किया जाएगा।
- ई-कुबेर 3.0: प्राथमिक नीलामी, सार्वजनिक ऋण प्रबंधन, केंद्रीय लेखा अनुभाग और वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) जैसी कार्यात्मकताओं से संबंधित भविष्य के मॉड्यूल के विकास की योजना बनाई गई है।
- डिजिटल भुगतान प्रणाली के लिए वैकल्पिक तंत्र : रिज़र्व बैंक वैकल्पिक भुगतान और संदेश प्रणालियों के विकास और नवाचार को जारी रखेगा। इसका विजन उन्नत क्षमताओं के साथ आधुनिक मानकों पर आधारित भुगतान और संदेश समाधान विकसित करना होगा।
- एआई गवर्नेंस नीति: कर्मचारियों, विक्रेताओं और तीसरे पक्ष के भागीदारों द्वारा एआई/मशीन लर्निंग (एमएल) प्रौद्योगिकियों के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए रिज़र्व बैंक के लिए एआई नीति फ्रेमवर्क शुरू किया जाएगा। डेटा हैंडलिंग, सहमति और सुरक्षा पर स्पष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करके, नीति एआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों का उपयोग

करते हुए रिज़र्व बैंक के संचालन की अखंडता को बनाए रखने का प्रयास करती है।

- 'bank.in' और 'fin.in' डोमेन के माध्यम से वित्तीय क्षेत्र में विश्वास बढ़ाना: डिजिटल भुगतान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए, रिज़र्व बैंक ने भारतीय बैंकों के लिए 'bank.in' विशेष इंटरनेट डोमेन शुरू करने की घोषणा की थी। इस पहल का उद्देश्य साइबर सुरक्षा खतरों और फ़िशिंग जैसी दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों को कम करना है; और सुरक्षित वित्तीय सेवाओं को सुव्यवस्थित करना है, जिससे डिजिटल बैंकिंग और भुगतान सेवाओं में विश्वास बढ़े। बैंकिंग प्रौद्योगिकी में विकास और अनुसंधान संस्थान (आईडीआरबीटी) विशेष रजिस्ट्रार के रूप में कार्य करेगा। बैंकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

4. निष्कर्ष

IX.51 2024-25 के दौरान, रिज़र्व बैंक ने भुगतान प्रणालियों की दक्षता, सुरक्षा और पहुँच को बढ़ाने की दिशा में अपने प्रयासों को जारी रखा, साथ ही वैश्विक पहुँच का और विस्तार किया, डिजिटल भुगतान अपनाने को बढ़ावा दिया और साइबर समुत्थानशीलता को मजबूत किया। नवाचार को बढ़ावा देने, परिचालन जोखिमों को कम करने और अपने आईटी सिस्टम और एप्लीकेशनों के सुचारू संचालन के लिए मजबूत आईसीटी बुनियादी ढाँचा सुनिश्चित करने की दिशा में प्रयास जारी रहे। वित्तीय क्षेत्र के लिए सी लाउड सुविधा, अगली पीढ़ी की कोर बैंकिंग (अर्थात, ई-कुबेर 3.0), 'bank.in' डोमेन के लिए बैंकों का पंजीकरण और एआई गवर्नेंस नीति ढांचा 2025-26 में शुरू किया जाएगा।